

मुख्य समाचार

- प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल खेलों इंडिया संवाद को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से करेंगे संबोधित।
- प्रदेश में आउटसोर्स पर स्टाफ नर्सों की भर्ती नहीं करेगी सरकार—कोविड महामारी में हटाए गए आउटसोर्स कर्मचारियों को दोबारा नियुक्त करने की व्यवस्था।
- राज्य के एक सौ 47 सी.बी.एस.ई. स्कूलों में 30 सितंबर तक कर दी जाएगी शिक्षकों की नियुक्ति— सौ और स्कूल होंगे सी.बी.एस.ई.।
- विधानसभा में राष्ट्रीय गीत पर विवाद को लेकर विपक्ष ने मुख्यमंत्री के खिलाफ दिया विशेषाधिकार हनन का नोटिस।
- मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने अगले शैक्षणिक सत्र से एडमिशन फॉर्म में जाति का कॉलम खत्म करने के दिए निर्देश।

प्रधानमंत्री—खेलो इंडिया संवाद

प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी कल वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से खेलो इंडिया संवाद को संबोधित करेंगे। राष्ट्रीय खेल दिवस 2026 समारोह के अंतर्गत मेरा युवा भारत – माय भारत द्वारा आयोजित यह कार्यक्रम देश भर में राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के प्रत्येक जिले के दो कॉलेजों में युवाओं की भागीदारी के साथ आयोजित किया जाएगा। कार्यक्रम के बाद युवा प्रतिभागियों, माय भारत के स्वयंसेवकों, स्थानीय खिलाड़ियों और जन प्रतिनिधियों के साथ स्थानीय स्तर पर संवाद होगा।

प्रश्नकाल

मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने ऐलान किया है कि सरकार स्वास्थ्य क्षेत्र में आउटसोर्स भर्ती को कम करेगी और मेडिकल कॉलेजों में स्टाफ नर्सों की नियुक्ति आउटसोर्स माध्यम से नहीं की जाएगी। शिमला में चल रहे प्रदेश विधानसभा के मॉनसून सत्र में आज प्रश्नकाल के दौरान मुख्यमंत्री ने विधायक दीपराज के सवाल के जवाब में ये जानकारी दी। उन्होंने कहा कि नर्सों की भर्ती लिखित परीक्षा के माध्यम से की जाएगी और अगले चार-पांच महीने में सभी मेडिकल कॉलेजों में योग्य नर्सों की तैनाती का लक्ष्य रखा गया है। मुख्यमंत्री ने कहा कि कोविड-19 महामारी के दौरान टांडा मेडिकल कॉलेज और आईजीएमसी में आउटसोर्स आधार पर रखे गए कर्मचारियों को दोबारा नियुक्त करने की व्यवस्था की गई है। उन्होंने कहा कि भविष्य में सभी भर्तियां राज्य चयन आयोग के माध्यम से की जाएगी। जिससे कर्मचारियों के नियमितकरण में कोई बाधा न आए। उन्होंने यह भी स्पष्ट किया कि जलवाहक और पैरा-फिटर कर्मचारियों की नियुक्ति आउटसोर्स माध्यम से नहीं होती, ये विभागीय नीति के तहत लगाए जाते हैं। मुख्यमंत्री ने कहा कि आउटसोर्स कर्मचारियों को नीति के अनुसार मिलने वाले लाभ दिए जाने जरूरी हैं और यदि किसी आउटसोर्स एजेंसी ने कर्मचारियों के वेतन में गलत तरीके से कटौती की है तो सरकार को इसकी जानकारी देने पर कार्रवाई करेगी। विधायक रणधीर शर्मा के सवाल के जवाब में मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रदेश के एक सौ 47 सीबीएसई स्कूलों में 30 सितंबर तक शिक्षकों की नियुक्ति कर दी जाएगी। उन्होंने कहा कि सरकार का जोर सरकारी स्कूलों में शिक्षा की गुणवत्ता सुधारने और बच्चों की संख्या बढ़ाने पर है। मुख्यमंत्री ने बताया कि इन सीबीएसई स्कूलों में शिक्षकों की नियुक्ति के लिए योग्यता के मानक तय किए गए हैं और चयन में मेरिट 80 प्रतिशत तक रही है। मुख्यमंत्री ने कहा कि सरकार सौ और स्कूलों को सीबीएसई से जोड़ेगी और दूसरे चरण में अन्य स्कूलों को भी इस व्यवस्था में लाने पर विचार किया जाएगा। नेता प्रतिपक्ष

जयराम ठाकुर, विधायक रणधीर शर्मा, राकेश जमवाल और हंसराज ने भी आउटसोर्स कर्मचारियों से संबंधित सवाल पूछे। उन्होंने आरोप लगाया कि सरकार ने बेरोजगारों को रोजगार देने के बजाय बड़ी संख्या में आउटसोर्स एजेंसियां और ठेकेदार तैयार कर दिए हैं।

राष्ट्र गान विवाद

प्रदेश विधानसभा में राष्ट्रगान और राष्ट्रगीत को लेकर शुरू हुआ विवाद अब मुख्यमंत्री के खिलाफ विशेषाधिकार हनन के नोटिस तक पहुंच गया है। विपक्ष ने आज मुख्यमंत्री के खिलाफ विधानसभा अध्यक्ष को विशेषाधिकार हनन का नोटिस दिया है। दूसरी तरफ कांग्रेस का आरोप है कि भाजपा अपनी गलतियों को सुधारने के लिए तरह-तरह के हथकंडे अपना रही है। विस्तृत ब्यौरे के साथ हमारे विशेष संवाददाता.....

प्रदेश विधानसभा में राष्ट्र गान और राष्ट्रीयगीत के कथित अपमान को लेकर शुरू हुआ विवाद अब और गरमा गया है। विधानसभा सचिवालय की ओर से जारी वीडियो को लेकर नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर ने मुख्यमंत्री और कांग्रेस सरकार पर झूठ बोलने का आरोप लगाया है। उन्होंने दावा किया कि वीडियो सामने आने के बाद साफ हो गया है कि राष्ट्र गान का किसी भी तरह से अपमान नहीं हुआ है और इस संबंध में मुख्यमंत्री व कांग्रेस नेताओं की ओर से लगाए गए आरोप गलत साबित हुए हैं। जयराम ठाकुर ने कहा कि विपक्ष ने मुख्यमंत्री के खिलाफ आज विधानसभा अध्यक्ष को विशेषाधिकार हनन का नोटिस दिया गया

वहीं भाजपा के विशेषाधिकार हनन प्रस्ताव पर प्रतिक्रिया देते हुए मुख्यमंत्री सुखविंद्र सिंह सुक्खू ने कहा कि भाजपा अपनी गलतियों को सुधारने के लिए तरह-तरह के हथकंडे अपना रही है। उन्होंने दोहराया कि भाजपा ने राष्ट्र गान का अपमान किया है। मुख्यमंत्री ने कहा कि भाजपा नेताओं द्वारा लगातार झूठे आरोप लगाए जा रहे हैं और यदि यह सिलसिला जारी रहा तो कांग्रेस भी भाजपा के खिलाफ विशेषाधिकार हनन प्रस्ताव लाएगी। ..बाईटकू

मुख्यमंत्री...

विधानसभा के मानसून सत्र के पहले दिन राष्ट्रीय गीत और राष्ट्र गान के कथित अपमान के मुद्दे पर सियासत तेज हो गई है। इस मुद्दे को लेकर सत्ता पक्ष व विपक्ष दोनों एक दूसरे पर निशाना साध रहे हैं।

रितेश कपूर आकाशवाणी समाचार शिमला

सुक्खू

मुख्यमंत्री सुखविन्द्र सिंह सुक्खू ने अगले शैक्षणिक सत्र से एडमिशन फॉर्म में जाति का कॉलम खत्म करने के निर्देश दिए हैं। हिमाचल प्रदेश अनुसूचित जाति कल्याण बोर्ड की आज शिमला में आयोजित बैठक की अध्यक्षता करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि सरकार समाज में जाति के नाम पर भेदभाव को खत्म करने का प्रयास कर रही है। उन्होंने कहा कि स्कूल के दाखिला फॉर्म में जाति का कॉलम खत्म करना इस दिशा में एक शुरुआत होगी ताकि बच्चे किसी हीनभावना से ग्रस्त न हों। उन्होंने कहा कि सरकारी योजनाओं का लाभ लेने के लिए अनुसूचित जाति समुदाय के लोग अपनी जाति का कॉलम भर सकेंगे ताकि उन्हें इन योजनाओं लाभ निर्बाध प्राप्त होता रहे।

बिट्टू शर्मा

मुख्यमंत्री के राजनीतिक सलाहकार सुनील शर्मा बिट्टू ने आज हमीरपुर ज़िला के उखली गांव में वन विभाग द्वारा आयोजित वन महोत्सव कार्यक्रम में बतौर मुख्य अतिथि हिस्सा लिया। इस अवसर पर सुनील शर्मा बिट्टू ने कहा कि हिमाचल प्रदेश जैसे पहाड़ी राज्य की वन संपदा हमारी अमूल्य धरोहर ही नहीं, बल्कि यह प्रदेश की जलवायु का संरक्षण भी करती है। उन्होंने वनों के संरक्षण और अधिक से अधिक पौधारोपण करने पर बल दिया। सुनील शर्मा बिट्टू ने बताया कि मुख्यमंत्री सुखविंद्र सिंह सुक्खू ने प्रदेश के वनों के संरक्षण के साथ-साथ पौधारोपण के माध्यम से स्थानीय लोगों को रोजगार प्रदान करने की दिशा में राजीव गांधी वन संवर्द्धन योजना आरंभ की है। उन्होंने बताया कि इस योजना के तहत ग्राम पंचायतों, महिला मंडलों और युवक मंडलों को पौधारोपण व इन पौधों की देखभाल के लिए वित्तीय सहायता प्रदान की जा रही है। इससे प्रदेश का हरित आवरण बढ़ेगा और स्थानीय लोगों को रोजगार भी मिलेगा।